GEO IAS
It's about quality

7-8 July 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | PIB | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 7-8 July 2024

Important News Articles

1. लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व-द हिंदू
2. DRDO ने देश के स्वदेशी टैंक जोरावर का अनावरण किया- द हिंदू
3. फार्मा क्षेत्र ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर राहत और प्रोत्साहन की मांग की- द हिंदू
4. सज़ा के तौर पर ज़मानत नहीं रोकी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू
5. भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग: प्रोत्साहन और प्रमुख प्रतिभागी- द हिंदू
6. ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बेकी के मार्ग बदलने के कारण असम में बाढ़ का संकट उत्पन्न हुआ - डाउन टू अर्थ
7. GIFT सिटी के माध्यम से UAE से चांदी के आयात पर संकट -द हिंदू
8. तिब्बती पठार पर विलुप्त मानव प्रजाति डेनिसोवन के जीवाश्म की पहचान की गई- द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

9. निम्न-कार्बन जलवायु अनुकूल विकास पर कानून- द हिंदू
10. महिला श्रमबल में कम भागीदारी विकास में बाधा: RBI ED-द हिंदू

Quick Look

1. हेपेटाइटिस A
2. आषाढ़ी बीज
3. जीनोम संपादन
4. ट्रांसपोज़न
5. ग्राफीन

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन I

1. लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व-द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- महिला आरक्षण विधेयक

प्रासंगिकता: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

समाचार:
- वर्ष 1952 में हुए प्रथम संसदीय चुनाव के बाद से लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया है।

मुख्य बिंदु
- पहली लोकसभा में कुल 489 सांसदों में से 22 महिला सांसद थीं, जो कुल सांसदों का 4.5% हिस्सा था।
- वर्ष 1957 में 494 सांसदों में से 27 महिलाएं (5.5%) थीं।
- 17वीं लोकसभा में, जिसमें 543 सांसद थे, 78 महिलाएं (14.4%) थीं।
- वर्ष 2024 के चुनाव के बाद गठित 18वीं लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से 74 महिला सांसद (13.6%) होंगी।
- वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के मामले में राजनीतिक दलों के बीच बमुश्किल कोई अंतर था।

सामान्य अध्ययन II

2. DRDO ने देश के स्वदेशी टैंक जोरावर का अनावरण किया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- DRDO
- DAC

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन

समाचार:
- देश के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का प्रोटोटाइप तैयार है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा।
- इस टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा प्रमुख इंटीग्रेटर लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

मुख्य बिंदु:
- यह टैंक वर्तमान में कमिंस इंजन द्वारा संचालित है, और DRDO ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है।
- इसे न्यूनतम समय में विकसित किया गया है तथा यह पृथ्वी पर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी संचालन करने में सक्षम है:
  - उत्तरी सीमा पर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यंत खराब मौसम और अत्यधिक ऊंचाई के साथ न्यूनतम सैन्य सहायता।
- फैक्ट्री स्वीकृति के बाद पहला प्रोटोटाइप तैयार है।
- इस टैंक को अगस्त 2025 तक परीक्षण के लिए सेना को सौंपने की योजना है।
- सूत्रों ने बताया कि DRDO ने हल्के टैंक के लिए पावर पैक विकसित करने की परियोजना शुरू की है, जबकि अर्जुन Mk1A मुख्य युद्धक टैंक के लिए एक नया 1,400 HP इंजन भी विकसित किया जा रहा है।
- इसके बाद, DRDO और L&T ने कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से एक हल्का टैंक विकसित करने के लिए मिलकर काम किया, जिन्हें उद्योग के माध्यम से रक्षा हथियार प्लेटफार्मों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उप-प्रणाली विकास के लिए शामिल किया गया है।

3. फार्मा क्षेत्र ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर राहत और प्रोत्साहन की मांग की- द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- फार्मा निर्यात
- PLI योजना

समाचार:
- भारत की दवा कम्पनियां नई दवाओं पर अनुसंधान के लिए कर प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि सरकार 23 जुलाई को प्रस्तुत किए जाने वाले इस वर्ष के केन्द्रीय बजट की तैयारी कर रही है।

मुख्य बिंदु
- यदि देश को अपनी किफायती दवाओं के लिए 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में प्रसिद्ध बनाए रखना है, तो भारतीय दवा निर्माताओं को जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर जटिल दवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
- उन्होंने कहा, "यदि सरकार भारत में विकसित नये अणुओं के लिए 5-10 वर्षों के लिए कुछ आयकर छूट दे सकती है।
  - जो नवाचार को जमीनी स्तर तक ला सके
  - कंपनियाँ नवाचार में निवेश करना शुरू करेंगी
- भारत का दवा बाजार वर्ष 2030 के अंत तक 130 बिलियन डॉलर का होने की उम्मीद है। यह अमेरिका और चीन के बाद मात्रा की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता है और जेनेरिक दवा निर्माताओं का केंद्र है।

कोई PLI योजना नहीं
- भारत ने ड्रोन से लेकर दवाओं तक के विनिर्माण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 से उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों की पेशकश की है। लेकिन नवीन दवा निर्माता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- मुझे लगता है कि सरकार इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि उनकी मौजूदा योजना किस प्रकार काम कर रही है, लेकिन उद्योग जगत अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाली नीति की अपेक्षा कर रहा है।
- भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, भारत का निर्यात, जो अमेरिकी जेनेरिक बाजार पर हावी है, वर्ष 2030 तक दोगुना होकर 55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

4. सज़ा के तौर पर ज़मानत नहीं रोकी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुच्छेद 21

समाचार:
- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अपराध की प्रकृति चाहे जो भी हो, किसी भी आरोपी की जमानत के अधिकार को दंड के रूप में रोका नहीं जा सकता।

मुख्य बिंदु
- यदि राज्य, अभियोजन एजेंसियां या यहां तक कि अदालतों के पास किसी अभियुक्त के शीघ्र सुनवाई के अधिकार की रक्षा करने के लिए साधन नहीं हैं, तो उन्हें इस आधार पर जमानत नहीं रोकनी चाहिए कि कथित अपराध गंभीर है।
- जमानत देने से इनकार करना एक अन्यायपूर्ण सजा है, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को "कारावास" में डाल दिया जाता है, जबकि दोषी साबित होने तक वह निर्दोष होता है।
  - संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना लागू होता है
- यह आदेश जावेद गुलाम नबी शेख द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आधारित था, जिसमें उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के प्रावधानों के तहत एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को स्थगित करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और शेख को उसकी स्वतंत्रता वापस देने का फैसला किया।
- पीठ ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद है।
- न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत अब तक इस मामले में आरोप तय करने में भी सक्षम नहीं हो सकी है।

सामान्य अध्ययन III

5. भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग: प्रोत्साहन और प्रमुख प्रतिभागी- द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- PLI योजना
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

समाचार:
- भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला को गहरा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि केंद्र ने पहले ही एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए ₹76,000 करोड़ के प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत लगभग ₹70,000 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है।

मुख्य बिंदु:
- भारत का प्रोत्साहन कार्यक्रम दुनिया की सबसे उदार पहलों में से एक है। केंद्र की ओर से 50% प्रोत्साहन के अतिरिक्त, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी-अपनी नीतियों के माध्यम से अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया है।
- इसलिए, इकाई स्थापित करने की लागत का 75% सब्सिडी पर दिया जाता है।
- उन्होंने कहा कि शेष राशि [₹76,000 करोड़ में से] वर्ष 2021 में घोषित भारत सेमीकंडक्टर मिशन कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्ध की जाएगी
- भारत के 110 बिलियन डॉलर के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में से, असेंबली और श्रम कारकों के कारण लगभग 18-20% मूल्य संवर्धन हुआ।
- यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- हालांकि, ज्यादातर, यह श्रम लागत के मामले में मध्यस्थता पर आधारित असेंबली अभ्यास है। जबकि यह रोजगार प्रदान करता है, अगर हम मूल्य श्रृंखला को गहरा नहीं करते हैं तो जोखिम है। यह किसी अन्य देश में जा सकता है जो सस्ता श्रम प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि देश में अधिक घटकों का विनिर्माण हो।
- यह वह जगह है जहां केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के डिजाइन पर भारत सफल रहा है, जहां वैश्विक डिजाइन कार्यबल का अनुमानतः 20-25% हिस्सा देश से बाहर आधारित है।

परिशुद्धता के बारे में सब कुछ
- हालाँकि, विनिर्माण की बात करें तो स्थिति अलग है।
- सेमीकंडक्टर का मतलब है सटीक निर्माण, शून्य त्रुटि और सटीकता प्राप्त करने के लिए सब कुछ परमाणु स्तर तक ले जाना। यह कुछ ऐसा है जो हमें ताइवान, कोरिया और जापान से सीखने की जरूरत है।
- हमें उस सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन प्रदान करना होगा, जिसका उद्देश्य यही है।

6. ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बेकी के मार्ग बदलने के कारण असम में बाढ़ का संकट उत्पन्न हुआ - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- बेकी नदी

समाचार:
- ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बेकी के मार्ग बदलने और दक्षिण असम में हजारों लोगों तथा एक राज्य राजमार्ग को विस्थापित करने के लिए मानवीय गलतियाँ और अज्ञानता जिम्मेदार है।

बेकी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण
- विश्व बैंक द्वारा समर्थित वर्ष 2022 की एकीकृत बाढ़ एवं कटाव प्रबंधन योजना ने बेकी नदी के मार्ग में बढ़ते बाढ़ के खतरे और गंभीर कटाव पर प्रकाश डाला है।
- भूटान में कुरिचू बांध से समय-समय पर पानी छोड़े जाने से बाढ़ और कटाव में वृद्धि हुई, जिससे बेकी का प्राकृतिक मार्ग काफी हद तक बदल गया।
- सक्रिय बैंक संरक्षण उपायों की कमी तथा जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय में विफलता ने संकट को और बढ़ा दिया।

7. GIFT सिटी के माध्यम से UAE से चांदी के आयात पर संकट -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- GIFT सिटी
- GTRI

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- भारत में चांदी का लगभग पूरा आयात अब कुछ निजी प्रतिभागियों द्वारा किया जा रहा है, जो दुबई से GIFT सिटी एक्सचेंज के माध्यम से सफेद धातु लाते हैं।
  - जिससे समय के साथ राजकोष को भारी राजस्व हानि हो सकती है।

मुख्य बिंदु

- एक व्यापार अनुसंधान निकाय ने निर्यात और आयात फर्मों के बीच संबंधों की जांच की मांग की है ताकि किसी भी संभावित हितों के टकराव की पहचान की जा सके और उसका समाधान किया जा सके
  - साथ ही चेतावनी दी कि चांदी बाजार का यह रुझान सोने, प्लैटिनम और हीरे तक फैल सकता है, जिससे पारंपरिक आयात गतिविधियों और बाजार की गतिशीलता में और अधिक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- UAE से भारत का सोने और चांदी का आयात वर्ष 2023-24 में 210% बढ़कर 10.7 बिलियन डॉलर हो गया।
- कुल चांदी का आयात 5.4 बिलियन डॉलर रहा।
- मई में भारत के वैश्विक चांदी आयात का 87% हिस्सा दुबई से 8% कम शुल्क पर आया और गांधीनगर में GIFT सिटी एक्सचेंज के माध्यम से निकासी की गई।
  - जो दिसंबर 2023 से UAE से सभी चांदी के आयात को मंजूरी दे रहा है। अन्य देशों और बंदरगाहों से आयात लगभग छोड़ दिया गया है।
- थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने एक रिपोर्ट में कहा कि इससे पहले कुछ बैंकों द्वारा अन्य बंदरगाहों के माध्यम से UAE से चांदी आयात करने के प्रयासों पर भारत-UAE मुक्त व्यापार समझौते के मूल नियमों का पालन नहीं करने के कारण सवाल उठाए गए थे।
- "मुख्य चिंता यह है कि GIFT सिटी के माध्यम से किए जाने वाले आयात भारत-UAE CEPA [व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते] में निर्दिष्ट मूल आवश्यकताओं के नियमों को कैसे पूरा करते हैं
- जब अन्य बंदरगाहों से आयातक इन शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं
- भारत चांदी पर 15% आयात शुल्क लगाता है और केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा नामित संस्थाओं को ही इस बहुमूल्य धातु के आयात की अनुमति देता है।
- हालांकि, GIFT सिटी एक्सचेंज आयात को RBI/DGFT-नामित एजेंसियों तक सीमित नहीं रखता है, निजी व्यापारियों को पंजीकृत करता है, तथा उसे अन्यत्र सीमा शुल्क द्वारा चिह्नित मूल नियमों से संबंधित कोई समस्या नहीं मिली है।

शून्य टैरिफ

- 2022 में हस्ताक्षरित CEPA के तहत, भारत ने 10 वर्षों में चांदी के आयात पर शुल्क को घटाकर 0% करने पर सहमति व्यक्त की है, बशर्ते कि दुबई के निर्यातक मूल नियमों की शर्तों को पूरा करें।
- "चूंकि अगले आठ वर्षों में टैरिफ शून्य हो जाएगा, इसलिए सभी चांदी का आयात संभवतः संयुक्त अरब अमीरात से होगा, जिसके परिणामस्वरूप 6,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा।
- इसने गलत तरीके से आयात किए जाने के जोखिम को कम करने के लिए चांदी के आयात को RBI और DGFT द्वारा अधिकृत नामित एजेंसियों तक सीमित करने का भी सुझाव दिया था।

8. तिब्बती पठार पर विलुप्त मानव प्रजाति डेनिसोवन के जीवाश्म की पहचान की गई- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- डेनिसोवंस
- बैशिया कार्स्ट गुफा

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर प्रभाव।

समाचार:

- प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, समुद्र तल से 3,280 मीटर ऊपर एक तिब्बती गुफा में पाए गए अस्थि अवशेष संकेत देते हैं कि मनुष्यों का एक प्राचीन समूह कई सहस्राब्दियों तक वहां जीवित रहा था।

मुख्य बिंदु:

- डेनिसोवंस प्राचीन मानव की एक विलुप्त प्रजाति है जो निएंडरथल और होमो सेपियंस के समान समय और उन्हीं स्थानों पर रहती थी।
- पुरातत्वविदों द्वारा अब तक केवल मुट्ठी भर डेनिसोवन अवशेषों की खोज की गई है।
- इस समूह के बारे में बहुत कम जानकारी है, यहां तक कि यह भी कि वे कब विलुप्त हो गए, लेकिन ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि उन्होंने निएंडरथल और होमो सेपियंस दोनों के साथ प्रजनन किया था।
- जिस परत में यह पसलियां पाई गई थीं, उसका काल 48,000 से 32,000 वर्ष पुराना बताया गया है, जिसका अर्थ है कि यह डेनिसोवन व्यक्ति उस समय रहता था जब आधुनिक मानव यूरेशियाई महाद्वीप में फैल रहा था।
- परिणामों से पता चलता है कि डेनिसोवैन लोग दो ठंडे कालखंडों में जीवित रहे, लेकिन मध्य और उत्तर प्लीस्टोसीन युगों के बीच एक गर्म अंतरहिमनद काल में भी जीवित रहे।
- अनुसंधान दल ने उच्च ऊंचाई वाले तिब्बती पठार पर स्थित बैशिया कार्स्ट गुफा से 2,500 से अधिक हड्डियों का अध्ययन किया। यह उन दो स्थानों में से एक है जहां डेनिसोवांस के रहने की बात ज्ञात है।
- उनके नए विश्लेषण ने एक नए डेनिसोवन जीवाश्म की पहचान की है और इस प्रजाति की 200,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तिब्बती पठार पर हिमयुग सहित परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता पर प्रकाश डाला है।
- टीम ने एक नवीन वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया, जो पशुओं के बीच अस्थि कोलेजन में अंतर का उपयोग करके यह निर्धारित करती है कि अस्थि अवशेष किस प्रजाति से आए हैं।
- अनुसंधान दल ने निर्धारित किया कि अधिकांश हड्डियां नीली भेड़, जिसे भारल के नाम से जाना जाता है, के साथ-साथ जंगली याक, इक्विड, विलुप्त ऊनी गैंडे और धब्बेदार लकड़बग्घे की थीं।
- शोधकर्ताओं ने छोटे स्तनधारियों, जैसे मर्मोट और पक्षियों की हड्डियों के टुकड़ों की भी पहचान की है ।
- टीम यह पहचानने में सफल रही कि डेनिसोवांस कई प्रकार के जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें मारते थे और खाते थे।
- खंडित हड्डियों की सतहों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि डेनिसोवावासी हड्डियों से मांस और अस्थि मज्जा निकालते थे, लेकिन यह भी संकेत मिलता है कि मनुष्यों ने उनका उपयोग औजार बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया था।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. निम्न-कार्बन जलवायु अनुकूल विकास पर कानून- द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

समाचार:

- एमके रंजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने" के अधिकार को मान्यता दी और इसे जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार से प्राप्त किया।
- इन न्यायिक हस्तक्षेपों का एक टुकड़ा जलवायु परिवर्तन के लिए अपेक्षित व्यापक और प्रणालीगत दृष्टिकोण से वंचित रह जाएगा।
- इसलिए, भारतीय संदर्भ के अनुरूप जलवायु कानून का मजबूत मामला समय की मांग है।

विकास विकल्पों को सूचित करने वाला कानून	भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?
• जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने तथा इसके प्रभावों से निपटने के लिए भारत को तैयार करने हेतु विकास को निम्न-कार्बन तथा जलवायु-सघन भविष्य की ओर पुनः उन्मुख करना आवश्यक है। • जलवायु परिवर्तन लगातार कमजोर तबकों को निशाना बनाता है, और चूंकि ऊर्जा परिवर्तन न्यायसंगत होना चाहिए, इसलिए इसे सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की अनिवार्यता पर आधारित होना चाहिए। • यद्यपि जलवायु कानून की अवधारणा को अक्सर लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के शीर्ष-स्तरीय दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है, लेकिन विकासशील देशों में यह दृष्टिकोण सीमित है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटना उत्सर्जन को सीमित करने से कहीं अधिक है। • इसके बजाय, इसके लिए प्रत्येक विकासात्मक विकल्प तथा निम्न-कार्बन और जलवायु लचीले भविष्य के साथ इसके दीर्घकालिक तालमेल और समझौतों पर सावधानीपूर्वक, निरंतर विचार करने की आवश्यकता है। • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा के मूलभूत अधिकार को, आंशिक रूप से, कानून में सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, जो सरकार के सभी स्तरों पर लागू हों। • कई देशों (एक अनुमान के अनुसार 67) ने 'ढांचागत जलवायु कानून' के साथ प्रयोग किया है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शासन क्षमता का निर्माण करते हैं। • व्यापक कानून जो सरकार-व्यापी लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं तथा उन्हें प्रक्रियाओं और जवाबदेही उपायों के एक सेट के साथ पुष्ट करते हैं, जलवायु कार्रवाई को सरकार के केंद्र में लाने का एक ज्ञात और तेजी से लोकप्रिय तरीका है। • हालाँकि, ये कानून अलग-अलग हैं, और भारत का दृष्टिकोण हमारे संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए।	• प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के निम्न आधार से शुरू होकर, जो वैश्विक औसत के आधे से भी कम है, भारत का उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है • हमारा उद्देश्य प्रत्येक टन कार्बन से यथासंभव अधिकतम विकास प्राप्त करना तथा उच्च कार्बन भविष्य में फंसने से बचना होना चाहिए। • इसके अलावा, भारत जलवायु प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और जलवायु लचीलापन नए कानून का एक अनिवार्य तत्व होना चाहिए। • दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में सामाजिक समानता का विचार केन्द्रीय होना चाहिए। • परिणामस्वरूप, भारत के कानून को विकास सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन कम कार्बन की दिशा में, साथ ही अधिक व्यापक जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन विकसित करना चाहिए। **कम कार्बन विकास निकाय रखें** • तात्कालिक प्राथमिकता सरकार में एक ज्ञान निकाय का निर्माण करना है जो नीति विकल्पों और उनसे उत्पन्न होने वाले भविष्य का गहन विश्लेषण करने में सक्षम हो। • विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों से युक्त एक स्वतंत्र 'निम्न-कार्बन विकास आयोग', जो राष्ट्रीय और राज्य दोनों सरकारों को निम्न-कार्बन विकास और लचीलापन प्राप्त करने के व्यावहारिक तरीके सुझा सके। • यह निकाय विचार-विमर्शपूर्वक निर्णय लेने के लिए एक मंच के रूप में भी काम कर सकता है। ○ कमजोर समुदायों और तकनीकी परिवर्तन से नुकसान उठाने वाले लोगों से व्यवस्थित रूप से परामर्श किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- प्रभावी जलवायु शासन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने, रणनीतिक विकल्प बनाने, तथा संबंधित मंत्रालयों के भीतर निम्न कार्बन विकल्पों और जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर विचार को प्रोत्साहित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।
- दुनिया भर में जलवायु नीति अक्सर एकाकी निर्णय प्रक्रिया के कारण विफल हो जाती है।
  - इसलिए, यह कानून एक उच्च स्तरीय रणनीतिक निकाय का निर्माण कर सकता है, जो 'जलवायु कैबिनेट' हो सकता है, जिसका कार्य सरकार के माध्यम से रणनीति बनाना होगा।
- सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के लिए कार्यान्वयन हेतु समर्पित समन्वय तंत्र की भी आवश्यकता होगी।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून को भारत के संघीय ढांचे पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्सर्जन को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कई क्षेत्र, जैसे बिजली, कृषि, पानी, स्वास्थ्य और मिट्टी पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य और स्थानीय सरकारों के अधीन हैं।
- न्यायालय के नव स्थापित जलवायु अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए किसी भी संस्थागत स्ट्रक्चर या नियामक साधन को उप-राष्ट्रीय सरकारों के साथ सार्थक रूप से जुड़ना होगा।
- एमके रंजीतसिंह मामले में न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से कानूनी और प्रशासनिक बदलावों का द्वार खुल गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ कार्रवाई योग्य अधिकार संभव हो गया है।
- लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए, इस खुले दरवाजे का उपयोग वास्तव में एक जलवायु कानून पारित करने के लिए किया जाना चाहिए जो भारतीय संदर्भ के लिए उपयुक्त हो, जो भारतीय विकास विकल्पों को कम कार्बन और जलवायु लचीले भविष्य की ओर ले जाए, और जो न्याय को भी आगे बढ़ाए।

10. महिला श्रमबल में कम भागीदारी विकास में बाधा: RBI ED-द हिंदू

प्रासंगिकता: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

समाचार:

- रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि महिलाओं की श्रम शक्ति में कम भागीदारी वित्तीय समावेशन प्रयासों और व्यापक आर्थिक विकास में बाधा है।
- महिलाओं को ऋण आपूर्ति बढ़ाने की भी आवश्यकता है, तथा बताया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले कुल ऋणों में से केवल 7% ही महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए हैं।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वर्तमान चुनौतियाँ	**महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की योजनाएं**
1. **कम श्रम बल भागीदारी दर** : महिला (32.8%) और पुरुष (77%) भागीदारी दरों के बीच महत्वपूर्ण असमानता है। 2. **ऋण पहुंच में विसंगतियां** : MSME में महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों का हिस्सा लगभग पांचवां हिस्सा होने के बावजूद, केवल 7% MSME ऋण उन्हें आवंटित किए जाते हैं। 3. **लैंगिक असमानता** : 2022 विश्व आर्थिक मंच की लैंगिक अंतर रिपोर्ट में 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है, जहां लैंगिक असमानता पांच प्रतिशत से अधिक है। 4. **लैंगिक आधारित वेतन अंतर** : ऑक्सफैम इंडिया की वर्ष 2022 भेदभाव रिपोर्ट में व्यापक लैंगिक आधारित वेतन विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है, जो भर्ती और वेतन गतिविधियों में पूर्वाग्रहों के कारण और भी बढ़ गई हैं। 5. **वित्तीय समावेशन में बाधाएं** : इनमें सीमित पूंजी और सामाजिक मानदंडों जैसी संरचनात्मक चुनौतियां, साथ ही वित्तीय क्षेत्र में धारणाएं और पूर्वाग्रह शामिल हैं। **महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय** 1. **प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को संबोधित करना** : ऋण देने में पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए महिला उधारकर्ताओं के निष्पक्ष मूल्यांकन और उपचार को बढ़ावा देना। 2. **शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण** : आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। 3. **पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करना** : महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए उचित शर्तों पर ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना। 4. **महिला-नेतृत्व वाले MSME को समर्थन** : महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों की वृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अनुरूप समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना।	• **राष्ट्रीय महिला आयोग** : महिलाओं के अधिकारों और कल्याण से संबंधित मुद्दों की निगरानी और समाधान के लिए वर्ष 1992 में स्थापित किया गया। • **स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण** : 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा स्थानीय निकायों में निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। • **महिला आरक्षण अधिनियम 2023** : निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम से आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है। • **प्रधान मंत्री जन-धन योजना** : इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। • **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) अधिदेश** : बैंकों और सूक्ष्म ऋणदाताओं को महिला उद्यमियों सहित वंचित वर्गों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। • **RBI विनियम** : प्रत्येक जिले में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्रों को अनिवार्य बनाता है। • **अन्य पहल** : इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, समग्र शिक्षा, महिला शक्ति केंद्र (MSK) और मिशन शक्ति जैसी विभिन्न सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं, जो एकीकृत महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

फैक्ट फटाफट

1. हेपेटाइटिस A

- हेपेटाइटिस ए यकृत की सूजन है जो हल्के से लेकर गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है।
- हेपेटाइटिस A वायरस (HAV) दूषित भोजन और पानी के सेवन से या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैलता है।
- लगभग हर व्यक्ति हेपेटाइटिस A से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे आजीवन प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। हालांकि, हेपेटाइटिस A से संक्रमित लोगों का एक बहुत छोटा हिस्सा फुलमिनेंट हेपेटाइटिस से मर सकता है।
- हेपेटाइटिस ए संक्रमण का जोखिम सुरक्षित जल की कमी और खराब स्वच्छता एवं स्वास्थ्य देखभाल (जैसे दूषित और गंदे हाथ) से जुड़ा हुआ है।
- हेपेटाइटिस ए की रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है।

2. आषाढ़ी बीज

- यह हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पड़ता है।
- यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत से जुड़ा हुआ है।
- आषाढ़ी बीज के दौरान वातावरण में नमी की जांच की जाती है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल सबसे अच्छी होगी।

3. जीनोम संपादन

- जीनोम संपादन प्रौद्योगिकियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के DNA में परिवर्तन करने की अनुमति देता है।
- ये प्रौद्योगिकियां जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या संशोधित करने में सक्षम बनाती हैं।
- कई अलग-अलग जीनोम संपादन उपकरण विकसित किए गए हैं, जिनमें CRISPR-Cas9 सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रयुक्त उपकरण है।
- जीनोम संपादन के विविध अनुप्रयोग हैं, जिनमें आनुवंशिक विकारों के उपचार के लिए जीन थेरेपी, फसल प्रतिरोध में सुधार और कृषि में उपज शामिल है
- इसमें रोग प्रतिरोधी पशुधन विकसित करने और लक्षित कैंसर उपचारों के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं की इंजीनियरिंग करने की भी क्षमता है।

4. ट्रांसपोज़न

- ट्रांसपोसॉन या "जंपिंग जीन" DNA अनुक्रम हैं जो जीनोम के भीतर अपनी स्थिति बदल सकते हैं।
- ये उत्परिवर्तन पैदा कर सकते हैं, जीनोम के आकार को बदल सकते हैं, तथा जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं।
- ट्रांसपोज़न विकास, आनुवंशिक विविधता और जीन के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा आनुवंशिक अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
- इनकी खोज सबसे पहले बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्का में की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1983 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला।

5. ग्राफीन

- ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु-मोटी परत है जो षट्कोणीय जालक में व्यवस्थित होती है।
- यह ग्रेफाइट का निर्माण-खंड है (जिसका उपयोग अन्य चीजों के अलावा पेंसिल की नोकों में किया जाता है)।
- इसे पहली बार वर्ष 2004 में पृथक किया गया था।
- ग्रैफीन दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है; इसकी मोटाई सिर्फ़ एक परमाणु है, जो मानव बाल से दस लाख गुना पतला है। हालाँकि, यह बहुत मज़बूत है, स्टील और हीरे से भी ज़्यादा मज़बूत।
- यह ऊष्मा और बिजली का एक बेहतरीन संवाहक है। यह तांबे से बेहतर बिजली का संचालन करता है। यह लगभग पूरी तरह से पारदर्शी है, क्योंकि यह केवल 2% प्रकाश को अवशोषित करता है।
- यह गैसों के लिए अभेद्य है, यहां तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी।
- यांत्रिक शक्ति: इसका उपयोग अन्य सामग्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. हाल ही में खबरों में रहे जेंडर संवाद के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह DAY-NRLM के तहत एक राष्ट्रीय आभासी पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में मिशन के हस्तक्षेपों के बारे में लैंगिक दृष्टिकोण से अधिक जागरूकता उत्पन्न करना है।
2. इसके तहत हाल ही में 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारी और ग्रामीण SHG महिलाएँ महिला समूहों के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन जुड़ती हैं।
3. यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 2 और 3

Q2. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. DRDO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख एजेंसी है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है।
2. DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी।
3. DRDO का मिशन रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति हासिल करना है।
4. एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) DRDO की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का विकास करना है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1, 3, और 4
D. 1, 2, 3, और 4

Q3. भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है।
2. भारतीय दवा उद्योग सक्रिय दवा सामग्री (API) के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
3. सरकार ने आयातित API पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2, और 3

Q4. अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. अनुच्छेद 21 नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
2. इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
3. शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से लिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 2 और 3

Q5. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करना है।
2. यह योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6% तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना केवल भारतीय कंपनियों पर लागू है और विदेशी कंपनियां इससे बाहर हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q6. निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है?

1. सुबानसिरी
2. रोंगनाडी
3. सुवर्णरेखा

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 2 और 3

Q7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I : GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) शहर में एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थित है

कथन II: GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) की परिकल्पना केवल भारत के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में की गई है

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या नहीं है
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q8. 'डेनिसोवन' शब्द का उल्लेख कभी-कभी मीडिया में किस संदर्भ में किया जाता है?

A. एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म।
B. एक प्रारंभिक मानव प्रजाति।
C. पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक गुफा प्रणाली।
D. भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक काल।

Q9. जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ?

1. पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर सीमित रखना है।
2. महासागरीय अम्लीकरण, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है।
3. ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 2 और 3

Q10. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संकेतक है जिसका उपयोग किसी देश में बेरोजगारी को मापने के लिए किया जाता है?

A. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
B. सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
C. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)
D. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प A सही है।

व्याख्या

- जेंडर संवाद DAY-NRLM के तहत एक राष्ट्रीय आभासी पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में मिशन के हस्तक्षेपों के बारे में लैंगिक दृष्टिकोण से अधिक जागरूकता उत्पन्न करना है। अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह थीम 'नए भारत की नारी' के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। **(इसलिए कथन 1 सही है)**
- इसके अंतर्गत हाल ही में 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारी और ग्रामीण SHG महिलाएँ महिला समूहों के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन जुड़ीं। **(इसलिए कथन 2 सही है)**
- यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**

उत्तर : 2 विकल्प D सही है

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** DRDO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख एजेंसी है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है।
- **कथन 2 सही है:** DRDO की स्थापना 1958 में तीन प्रमुख रक्षा संगठनों को मिलाकर की गई थी।
- **कथन 3 सही है:** DRDO का मिशन वास्तव में रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति हासिल करना शामिल है।
- **कथन 4 सही है:** एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) DRDO की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का विकास करना है।

उत्तर : 3 विकल्प D सही है

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो सस्ती दवाओं की वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- **कथन 2 सही है:** भारतीय दवा उद्योग सक्रिय दवा सामग्री (API) के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, विशेष रूप से चीन जैसे देशों से।
- **कथन 3 सही है:** भारत सरकार ने आयातित API पर निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (KSM), दवा मध्यवर्ती (DI) और API के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है।

उत्तर : 4 विकल्प C सही है।

व्याख्या :

- अनुच्छेद 21 नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू होता है। **कथन 1 सही है।**
- मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है। **कथन 2 सही है।**
- शिक्षा का अधिकार न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अनुच्छेद 21 से लिया गया है और अनुच्छेद 21A के अधिनियमन का कारण बना। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 5 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- **कथन 2 सही है:** यह योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **कथन 3 गलत है:** इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना भारतीय कंपनियों तक सीमित नहीं है; यह भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए खुली है ताकि व्यापक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और भारतीय विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

उत्तर : 6 विकल्प A सही है

व्याख्या

- सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, रोंगनादी, डिक्रोंग, बुरोई, बोरगोंग, जियाभराली, धनसिरी (उत्तर) पुथिमारी, मानस, बेकी, ऐ, सोनकोश उत्तर की मुख्य सहायक नदियाँ हैं
- सुवर्णरेखा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। सुवर्णरेखा नदी झारखंड के रांची में नागरी गांव के पास से निकलती है।

उत्तर : 7 विकल्प C सही है

व्याख्या

- GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- इसमें एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) और एक विशिष्ट घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) स्थित है।
- गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) की परिकल्पना न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में की गई है।

उत्तर : 8 विकल्प B सही है

व्याख्या :

- पहली बार, वैज्ञानिकों को साइबेरिया के बाहर डेनिसोवंस नामक विलुप्त प्राचीन मानव वंश के जीवाश्म मिले हैं।
- डेनिसोवंस मानवों का एक विलुप्त समूह था जो निएंडरथल्स के करीबी थे।
- इन्हें मुख्य रूप से साइबेरिया के डेनिसोवा गुफा में पाए गए कुछ जीवाश्म टुकड़ों तथा एशिया भर के लोगों के DNA में मौजूद आनुवंशिक सुरागों से जाना जाता है।

उत्तर : 9 विकल्प C सही है

व्याख्या :

- पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, संभवतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। **कथन 1 सही है।**
- महासागरीय अम्लीकरण दुनिया के महासागरों द्वारा अतिरिक्त वायुमंडलीय $CO2$ के अवशोषण के कारण होता है, जिससे pH स्तर कम हो जाता है। **कथन 2 सही है।**
- ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से महासागरों में अधिक पानी आने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 10 विकल्प C सही है

व्याख्या

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बेरोज़गारी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है। यह कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के उस प्रतिशत को दर्शाता है जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश कर रही है।

GEO IAS It's about quality

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com